



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032022-234274
CG-DL-E-17032022-234274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 16, 2022/फाल्गुन 25, 1943

No. 139]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 16, 2022/PHALGUNA 25, 1943

इंडियन बैंक
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2022

एफ. नं. आईबी/जी-9/2020-21(ई).—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 के साथ पठित धारा 12 की उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इंडियन बैंक का निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 में आगामी संशोधन करने हेतु निम्नलिखित विनियम बना रहा है :-

- (1) इन विनियमों को इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2022 कहा जाएगा।
- (2) इन विनियमों में अन्यथा किए गए प्रावधानों को छोड़कर, ये विनियम 1 नवंबर, 2012 से लागू माने जाएंगे।
- इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 (इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) में, विनियम 3 में, खण्ड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

‘(एफ) “परिवार” से तात्पर्य है कि अधिकारी की पत्नी/पति, पूर्णतः आश्रित अविवाहित पुत्र/पुत्री (सौतेले और वैध रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले भाई या बहन, विधवा पुत्रियाँ एवं तलाक़शुदा या पति से अलग हुई आश्रित पुत्रियाँ, अविवाहित या तलाक़शुदा या परित्यक्त या विधवा या पति से अलग बहनें और अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता तथा विवाहित महिला अधिकारी के मामले में वे अपने नैसर्गिक माता-पिता या सास-ससुर को शामिल कर सकते हैं, किन्तु दोनों को नहीं;’।

स्पष्टीकरण – “पूर्ण आश्रित” से तात्पर्य परिवार के ऐसे सदस्य से है जिसकी मासिक आय रु.10,000 प्रति माह से अधिक न हो तथा पूर्णतः आश्रित माता-पिता के संबंध में यदि माता-पिता में से किसी एक की आय रु.10,000 प्रतिमाह से अधिक हो या दोनों की कुल मासिक आय रु.10,000 प्रति माह से अधिक हो, तो दोनों को अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

3. उक्त विनियम के विनियम 4 में, उप विनियम(6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(6) 1 नवंबर, 2012 से प्रभावी, प्रत्येक ग्रेड के लिए वेतनमान निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :

(ए) उच्च कार्यपालक ग्रेड

स्केल VII = रु.76520 – 2120/4 – 85000

स्केल VI = रु.68680 – 1960/4 – 76520

(बी) वरिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

स्केल V = रु.59170 – 1650/2 – 62470 – 1800/2 – 66070

स्केल IV = रु.50030 – 1460/4 – 55870 – 1650/2 – 59170

(सी) मध्य प्रबंधन ग्रेड

स्केल III = रु.42020 – 1310/5 – 48570 – 1460/2 – 51490

स्केल II = रु.31705 – 1145/1 – 32850 – 1310/10 – 45950

(डी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड

स्केल I = रु.23700 – 980/7 – 30560 – 1145/2 – 32850 – 1310/7 – 42020

स्पष्टीकरण - प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2012 को लागू वेतनमान के अंतर्गत आते हैं, उनके वेतन मान को 1 नवंबर, 2012 को इस उप विनियम में दिए गए वेतनमान में स्टेज-दर-स्टेज आधार पर फिट किया जाएगा, अथवा पहली स्टेज से संबंधित वेतनमान में समनुरूप वेतनमान में फिट किया जाएगा और समान्यतः वार्षिक तिथि पर वेतनवृद्धि देय होगी।

(7) उप-विनियम (1), (2), (3), (4) (5) और (6) में किसी भी बात का यह आशय नहीं होगा कि बैंक में हर समय, इन सभी ग्रेड में अधिकारी सेवारत होना अपेक्षित है।

(8) 1 नवंबर, 2012 से लागू, अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ते दिए जाएंगे :

स्केल I – III – मूल वेतन का 7.75 % + इस पर लागू महंगाई भत्ता

स्केल IV – V – मूल वेतन का 10% + इस पर लागू महंगाई भत्ता

स्केल VI – VII – मूल वेतन का 11% + इस पर लागू महंगाई भत्ता

यह भी कि इस विनियम में किसी भी बात का यह आशय नहीं होगा कि बैंक में हर समय इन सभी ग्रेड में अधिकारी सेवारत होना अपेक्षित है।

नोट : उप विनियम 8 में संदर्भित विशेष भत्ता और इस पर लागू महंगाई भत्ता, को सेवानिवृत्ति लाभों जैसे कि नई पेंशन स्कीम सहित पेंशन, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी में शामिल नहीं किया जाएगा।”

4. उक्त विनियम के विनियम 5 में,-

(i) उप विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उपविनियम (1), प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(1) विनियम 4 के उप विनियम (6) के प्रावधानों के अंतर्गत, 1 नवंबर, 2012 को और उस तिथि से, निम्नलिखित के अधीन वेतनवृद्धियां प्रदान की जाएंगी:-

(ए) विनियम 4 के उप विनियम (6) में उल्लिखित वेतनमानों में निर्धारित वेतनवृद्धियां, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन वार्षिक आधार पर मिलेंगी और जिस महीने में वेतनवृद्धि देय होगी उस माह की पहली तारीख को प्रदान की जाएगी;

(बी) स्केल I और स्केल II के अधिकारी, अपने संबंधित स्केल में अधिकतम पर पहुंचने के 1 वर्ष बाद, अगले उच्च स्तर में स्टेगनेशन वेतन वृद्धि सहित आगामी वेतन वृद्धि दी जाएगी जो निम्नानुसार खंड (सी) में निर्दिष्ट दक्षता स्तर को पार करने के अधीन है;

(सी) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल I के अधिकारी जो खंड (बी) के अनुसार मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II के वेतनमान के स्केल तक पहुँच गए हैं, वे प्रत्येक पूर्ण तीन वर्ष की सेवा के लिए चार स्टेगनेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे जिसमें से पहला दो रु.1310 प्रत्येक और उसके बाद के दो रु.1460 प्रत्येक के होंगे;

(डी) मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल II के अधिकारी, जो खंड (बी) के अनुसार मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III के वेतनमान तक पहुँच गए हैं, वे प्रत्येक पूर्ण तीन वर्ष की सेवा के लिए रु.1460 के तीन स्टेगनेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे और तीसरे स्टेगनेशन वेतनवृद्धि की प्राप्ति के दो वर्ष बाद रु.1460 के चौथी स्टेगनेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

यह भी कि तीसरे स्टेगनेशन वेतनवृद्धि की प्राप्ति के दो वर्ष या उससे अधिक पूर्ण करनेवाले अधिकारियों को 01 मई, 2015 से चौथा स्टेगनेशन वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा;

(ई) मूल मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III के अधिकारी अर्थात् जो मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल III में भर्ती हुए हैं या पदोन्नत किए गए हैं, प्रत्येक तीन पूर्ण सेवा वर्षों के लिए रु.1460 के तीन स्टेगनेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे और जिन अधिकारियों ने 01 मई, 2015 को तीसरी स्टेगनेशन वेतनवृद्धि प्राप्त करने के बाद दो वर्ष या उससे अधिक पूर्ण किए हैं, वे चौथे स्टेगनेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे और चौथे स्टेगनेशन वेतनवृद्धि की प्राप्ति के दो वर्ष बाद रु.1460 के पाँचवी स्टेगनेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि जो अधिकारी चौथे स्टेगनेशन वेतनवृद्धि प्राप्ति के दो वर्ष पूर्ण किए हैं उन्हें 01 मई, 2015 के प्रभाव से पाँचवीं स्टेगनेशन वेतनवृद्धि दी जाएगी;

(एफ) एसएमजी स्केल-IV के अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने पर तीन वर्ष के बाद 01 मई, 2015 के प्रभाव से लागू रु.1650 की एक स्टेगनेशन वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे;

यह भी कि उस अधिकारी को ऐसी वेतनवृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति ग्रहण करने से इंकार करता है।

“स्पष्टीकरण - इस उप विनियम के तहत अगले उच्च स्केल के ऐसे वेतनवृद्धि का तात्पर्य पदोन्नति नहीं है और अधिकारियों के विशेषाधिकार, परिलब्धि, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पदों के अनुसार जारी रहेंगे।”;

(ii) उप विनियमन (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (एफ) के बाद और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड को सम्मिलित किया जाएगा:-

“(जी) 1 नवंबर, 2012 को और उस तिथि से अन्य तथ्य समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतनवृद्धि की मात्रा निम्नांकित तालिका के अनुसार संशोधित होगी

तालिका

(1)	(2)
जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट - पार्ट I उत्तीर्ण कर लिया है	(i) अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के बाद रु.670 प्रतिमाह।
जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भागों को उत्तीर्ण कर लिया है	(i) अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.670 प्रति माह। (ii) अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के दो वर्ष बाद रु.1680 प्रति माह:

यह भी कि वेतन के अधिकतम स्तर तक पहुँचने के बाद भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स सर्टिफाइड एसोसिएट (पहला या दोनों भाग) अर्हता अधिकतम वेतनमान तक पहुँचने के बाद प्राप्त करनेवाले अधिकारी को ऐसे व्यावसायिक अर्हता प्राप्त करने की तिथि से व्यवसायिका अर्हता वेतन की पहली किस्त दी जाएगी और व्यावसायिक अर्हता वेतन के बाद की किस्तें व्यवसायिक अर्हता वेतन की प्रथम किस्त की तिथि के अनुसार दी जाएंगी।”;

(iii) उप विनियमन (3) में, खंड (ई) के तहत तालिका के बाद, निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा:-

“(एफ) 1 नवंबर, 2012 को और उस तिथि से अन्य तथ्य समान पर आवास किराया भत्ता सहित स्थायी व्यक्तिगत वेतन निम्नलिखित दर पर होगा तथा पूरी सेवा अवधि के लिए अवरुद्ध रहेगा :

तालिका

वेतनवृद्धि राशि (रु.)	वेतनवृद्धि राशि पर 01.11.2012 को महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक ने आवास सुविधा दी है, वहां कुल स्थायी व्यक्तिगत वेतन देय (रु.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

नोट:

- (i) स्थायी व्यक्तिगत भत्ता या स्थायी व्यक्तिगत वेतन इस विनियम के खण्ड (बी), (सी), (डी), (ई) एवं (एफ) में कॉलम (3) के अंतर्गत दर्शाए गए उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।
- (ii) आवास किराया भत्ता के लिए पात्र अधिकारियों के लिए स्थिर व्यक्तिगत भत्ता या स्थिर व्यक्तिगत वेतन खंड (एफ) के तहत तालिका के कॉलम (1) और (2) में निर्धारित राशि का योग होगा तथा संबंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया आवास किराया भत्ता विनियमन 4 के उप विनियम (2), (3), (4), (5) और (6) में निर्धारित संबंधित वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि के अनुसार होगा।
- (iii) केवल वे अधिकारी जो 01 नवंबर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में थे, वे नियुक्ति वेतन के अधिकतम स्केल तक पहुँचने के एक वर्ष बाद स्थिर व्यक्तिगत वेतन के लिए पात्र होंगे।
- (iv) 1 नवंबर, 1999 को और उस तिथि से स्थिर व्यक्तिगत वेतन जारी करने के कारण उप विनियमन (2) के स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक अर्हता वेतन जारी करने की अनुसूची में कोई बदलाव नहीं होगा:
यह भी कि व्यावसायिक अर्हता वेतनवृद्धि की कोई भी किस्त जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए बदल दी गई हो और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी करने के लिए निर्धारित की गई हो, उसे इस तारीख से अधिकारी को जारी किया जाएगा और व्यावसायिक अर्हता वेतनवृद्धि की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी किया जाएगा।
- (v) स्थिर व्यक्तिगत भत्ता या स्थिर व्यक्तिगत वेतन की वेतनवृद्धि राशि को सेवा निवृत्ति लाभ के लिए शामिल किया जाएगा।

(vi) इस उप विनियम के खण्ड (ए) के अनुसार जिस अधिकारी ने अग्रिम वेतनवृद्धि प्राप्त की है, वह स्केल के उच्चतम वेतनमान तक पहुँचने के एक वर्ष बाद उपर्युक्त खण्ड (बी), (सी), (डी), (ई) या (एफ) में उल्लिखित अनुसार, स्थिर व्यक्तिगत भत्ता या स्थिर व्यक्तिगत वेतन प्राप्त करेगा।”

5. उक्त विनियम के विनियम 21 में, उप विनियम (5) के बाद, निम्नलिखित उप विनियम जोड़े जाएंगे:-

“(6) 01 नवंबर 2012 को तथा उक्त तारीख से, अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार वर्ष 1960=100, वेतन के 0.10% की दर से तिमाही औसत में 4440 अंकों में प्रत्येक चार अंक की वृद्धि या कमी पर मंहगाई भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण - इस उप विनियम के उद्देश्य के लिए, -

(ए) मंहगाई भत्ता के उद्देश्य के लिए “वेतन” का अर्थ है स्टेगनेशन वेतनवृद्धि सहित मूल वेतन के साथ विशेष भत्ता से है;

(बी) विनियम 5 के उप विनियम (2) में स्पष्टीकरण के खंड (सी), (डी), (ई), (एफ) तथा (जी) में निर्धारित व्यावसायिक अर्हता भत्ता या व्यावसायिक अर्हता वेतन पर मंहगाई भत्ता दिया जाएगा।

6. उक्त विनियम के विनियम 22 में

(i) उप विनियम (1) के लिए, निम्न उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा:-

“(1) 01 नवंबर 2012 को तथा उक्त तारीख से -

(ए) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवास सुविधा दी गयी है, अधिकारी जिस वेतनमान में हो उसके प्रथम चरण के मूल वेतन का या आवास के मानक किराया का 0.75 प्रतिशत जो भी कम हो, वह राशि उससे वसूली जायेगी;

(बी) जहां बैंक के द्वारा अधिकारी को आवास सुविधा नहीं दी गयी है, वहां निम्नलिखित तालिका में निर्धारित दर पर वह आवास किराया भत्ता हेतु पात्र होगा, जो इस प्रकार है:-

तालिका

जहां कार्य स्थल निम्न में है	एच.आर.ए निम्न दर पर देय होगा
(1)	(2)
(i) मेज़र “ए” श्रेणी के शहर तथा समूह ए में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9.0%
(ii) क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र केन्द्र एवं गोवा राज्य	वेतन का 8.0%
(iii) अन्य स्थान	वेतन का 7.0%

यह भी कि यदि अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए की वास्तविक राशि में से, वह जिस वेतनमान में हो, उसके प्रथम चरण के वेतन का 0.75% घटाकर शेष बची राशि, उसे देय आवास किराया भत्ता होगी। तथापि उसे देय अधिकतम आवास किराया भत्ता, उपर्युक्त तालिका के खण्ड (2) के अनुरूप आवास किराया भत्ता का अधिकतम 150% होगी।

नोट: अधिकारियों के स्वामित्व के आवास की लागत से संबद्ध मकान किराया भत्ते हेतु उनका दावा, आवास किराया भत्ता के 150% तक सीमित रहेगा।”

7. उक्त विनियम के विनियम 23 में,-

(ए) उप विनियम (1), (2), (3), (4) व (5) के लिए, निम्न उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जायेगा जो इस प्रकार है:-

“(1) 01 नवंबर, 2012 को तथा उक्त तारीख से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम 1 में वर्णित स्थान पर सेवारत है, तो उस स्थान के लिए कॉलम 2 में उल्लिखित दर पर शहर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा:-

तालिका

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) क्षेत्र 1 तथा गोवा राज्य में स्थित स्थान	मूल वेतन का 4% अधिकतम रु. 870 प्रति माह के अधीन
(ii) पांच लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान तथा राज्यों की राजधानी और चंडीगढ़, पुदुच्चेरी एवं पोर्ट ब्लेयर	मूल वेतन का 3% अधिकतम रु. 600 प्रति माह के अधीन

(2) 1 नवंबर, 2012 को तथा उक्त तारीख से विशेष क्षेत्र भत्ता दर इस विनियम की सूची में निर्धारित अनुसार होगी.

“(3) 01 नवम्बर 2012 को तथा उक्त तारीख से यदि कोई अधिकारी समूह ए तथा समूह बी में परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्धारित किये जा रहे क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो वह समूह ए तथा समूह बी के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः रु.400 या रु.350 की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते का पात्र होगा।

(4) 01 जून 2015 को तथा उस दिन से यदि कोई अधिकारी अकादमिक वर्ष के मध्य में स्थानांतरित होता है तथा पूर्व के स्थान पर उसके एक या अधिक बच्चे विद्यालय या महाविद्यालय में पढ रहे हैं, तो वह जिस तारीख से नये स्थान पर रिपोर्ट करते हैं, उस तारीख से सभी बच्चों के सम्बन्ध में अकादमिक वर्ष की समाप्ति तक रु.1100 प्रति माह का मध्य अकादमिक वर्ष स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करेगा, परन्तु यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढना छोड़ देते हैं तो उस तरह का भत्ता बंद हो जायेगा।

(5) 01 जून 2015 को या उस तारीख से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है, तो उसे जिस पद पर प्रतिनियुक्त किया जा रहा है, वह उससे संबंधित परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है या वह अपने वेतन के अतिरिक्त अपने वेतन का 7.75 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त करेगा जो अधिकतम रु. 4000 प्रतिमाह होगा तथा वैसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है जो उस स्थान पर बैंक की सेवा में पदस्थ होने पर उसे प्राप्त होते हैं।

यह भी कि वह ऐसी संस्था में प्रतिनियुक्त होता है, जो उस स्थान पर स्थित है जहाँ वह प्रतिनियुक्ति के ठीक पूर्व तैनात था तो उसे वेतन का 4 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त होगा जो अधिकतम प्रति माह रु. 2000 होगा:

यह भी कि अधिकारी को संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह वेतन के 4 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते हेतु पात्र होगा जो अधिकतम प्रतिमाह रु. 2000 होगा;

(बी) उप विनियम (8) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

“(8) 01 नवंबर 2012 को तथा उक्त तारीख से यदि दिन में न्यूनतम दो घंटे के अंतराल सहित कार्यालयीन समय बांटा जाता है तो वह अधिकारी प्रतिमाह रु.200 की दर से विभक्त सेवा भत्ते हेतु पात्र होगा।”;

(सी) उप-विनियम (10) में,-

(ए) संख्या, अक्षर और शब्द "1 नवंबर 2007" के स्थान पर संख्या, अक्षर और शब्द "1 नवंबर 2012" प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(बी) तालिका को, निम्न तालिका से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"तालिका

स्थान (1)	दर (2)
(i) 1000 मीटर से अधिक किन्तु 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान और मर्कारा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु.750 प्रतिमाह के अधीन
(ii) 1500 मीटर से अधिक किन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु.1000 प्रतिमाह के अधीन
(iii) 3000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.2000 प्रतिमाह के अधीन

8. उक्त विनियम के विनियम 24 में,

(i) उप विनियमन (1) के लिए, निम्नलिखित उप विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(1) नवंबर 2012 को और इस तिथि से अधिकारी स्वयं तथा उनके परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा और वह अधिकारी के स्वयं के प्रमाण पत्र के आधार पर इस तरह के व्यय के विवरण प्रस्तुत कर नीचे दी गई तालिका में निर्धारित राशि का दावा कर सकता है: -

तालिका

ग्रेड (1)	प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम सीमा (2)
कनिष्ठ प्रबंधन एवं मध्य प्रबंधन वर्ग	रु.8000 प्रति वर्ष या खर्च की गयी राशि, जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबंधन एवं उच्च कार्यपालक वर्ग	रु.9050 प्रति वर्ष या खर्च की गयी राशि, जो भी कम हो

नोट : (i) एक अधिकारी को चिकित्सा सहायता हेतु दी जानेवाली राशि का उपभोग न कर उसे संचित करने की अनुमति दी जा सकती है परंतु यह राशि कभी भी ऊपर दी गई अधिकतम राशि के तीन गुणा से अधिक नहीं होगा; अथवा

(ii) वर्ष 2012 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के तहत चिकित्सा हेतु खर्चों की प्रतिपूर्ति दो महीने, यानी नवंबर 2012 और दिसंबर, 2012 के अनुपात में बढ़ाई जाएगी।

(1ए) एक अधिकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार स्वयं एवं अपने परिवार हेतु चिकित्सा बीमा सुविधा के लिए पात्र है।”

9. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

“(2) उप-नियमन (1) में निहित किसी भी विवरण के बावजूद, यह बैंक द्वारा तय किया जाए कि वह अधिकारी द्वारा भुगतान करने पर किसी अधिकारी को नवंबर 2012 के पहले दिन से, वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन का 0.75 प्रतिशत के बराबर राशि, या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, के आधार पर आवासीय सुविधा प्रदान करें:

यह भी कि अधिकारी को इस तरह के निवास पर फर्नीचर प्रदान किया जाता है, वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन के 0.15 प्रतिशत के बराबर की राशि, बैंक द्वारा उससे वसूल किया जाएगा:

यह भी कि जहां इस तरह के आवासीय सुविधा बैंक द्वारा प्रदान किए जाते हैं, बिजली, पानी, गैस और संरक्षण के शुल्क अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।”

10. उक्त विनियम के विनियम 33 में, उप विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(4) 01 जून, 2015 को और उस तिथि से जब कभी भी छुट्टी के लिए आवेदन किया गया है और इसे मना कर दिया गया हो ऐसे मामलों को छोड़कर विशेषाधिकार अवकाश दो सौ सत्तर दिनों से अधिक संचित नहीं किया जा सकता है।

यह भी कि विशेषाधिकार अवकाश को भुनाने की अधिकतम सीमा दो सौ चालीस दिनों तक प्रतिबंधित रहेगी:

यह भी कि यदि एक अधिकारी विशेषाधिकार अवकाश का लाभ लेने को इच्छुक है, तो आमतौर पर इस तरह के अवकाश का लाभ प्राप्त करने की सूचना उसे कम से कम पंद्रह दिन पूर्व ही देनी होगी।"

11. उक्त विनियम के विनियम 34 में, उप विनियम (3) के बाद, निम्नलिखित उप विनियम को सम्मिलित किया जाएगा :-

"(4) 01 जून, 2015 को और उस तिथि से, किडनी या अंग दान के लिए एक अधिकारी को उसकी सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान तीस दिनों तक का विशेष अवकाश दिया जा सकता है।"

12. उक्त विनियम के विनियम 36 में, उप विनियम (2) और (3) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(2) 25 मई, 2015 से प्रभावी, कानूनी रूप से निम्न नियमों और शर्तों के अधीन एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने के लिए एक निःसंतान महिला अधिकारी को उसकी सेवा के दौरान एक बार छह महीने की अधिकतम अवधि के लिए अवकाश दिया जा सकता है :-

(i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी;

(ii) बच्चे को गोद लेना एक उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से होना चाहिए और इस तरह के अवकाश की मंजूरी के लिए कर्मचारी को बैंक के समक्ष दत्तक विलेख प्रस्तुत करना होगा;

(iii) बायोलॉजिकल मदर को उन मामलों में भी अवकाश मिलेगा जहाँ बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो; और

(iv) सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान बारह महीनों के समग्र पात्रता के तहत छुट्टी का लाभ उठाया जाएगा।

(3) 25 मई, 2015 से प्रभावी, बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, अधिकतम साठ दिनों तक गर्भाशय उच्छेदन के मामले में भी अवकाश दिया जा सकता है।"

(4) मातृत्व अवकाश, जो मूल वेतनमान पर होगा, किसी महिला अधिकारी को किसी भी अवसर पर अधिकतम छः महीने की अवधि के लिए और उसकी सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने के लिए दिया जाएगा:

यह भी कि मिसकैरेज या गर्भपात या गर्भावस्था के समापन के लिए बारह महीनों की सम्पूर्ण अवधि के अंतर्गत ही अवकाश दिया जाएगा।

(5) 01 जून, 2015 से प्रभावी, अधिकतम दो जीवित बच्चों वाले पुरुष अधिकारी / कर्मचारी अपनी पत्नी के प्रसवावस्था के दौरान पंद्रह दिनों के पितृत्व अवकाश के पात्र होंगे। इस अवकाश को आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है:

इस अवकाश के लिए आवेदन बच्चे के जन्म की तारीख से पंद्रह दिन पहले या छः महीने बाद तक किया जा सकेगा।"

13. उक्त विनियम के विनियम 38 में, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"38. एक अधिकारी के संचित सभी प्रकार के अवकाश उसके इस्तीफे, सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा-मुक्त होने, बर्खास्तगी या सेवा समाप्ति ऐसे किसी भी स्थिति में स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, निम्नलिखित पर ध्यान दें:

यह भी कि कोई अधिकारी बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त हो, वह किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा संचित अधिकतम दो सौ चालीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश के बराबर की राशि का भुगतान पाने के लिए पात्र होगा:

यह भी कि जहाँ किसी एक अधिकारी के लिए दंड स्वरूप सेवानिवृत्ति को अनिवार्य किया गया है, वह किसी भी अवधि के लिए उसके द्वारा संचित अधिकतम दो सौ चालीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश के बराबर की राशि का भुगतान पाने के लिए पात्र होगा:

यह भी कि सेवा में रहते हुए यदि किसी अधिकारी की मृत्यु हो जाए तो उसके मृत्यु के दिन तक उसके द्वारा संचित अधिकतम दो सौ चालीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश के बराबर की राशि का भुगतान उसके कानूनी प्रतिनिधियों को करना देय होगा:

यह भी कि यदि कोई अधिकारी 1 अप्रैल, 2001 को या उसके बाद विनियमन 20 के उप विनियमन (2) में यथोचित सूचना देने के बाद सेवा से इस्तीफा देता है तो उन्हें सेवा समाप्ति की तिथि पर उनके द्वारा सेवकालीन संचित इस तरह के अवकाश के आधे हिस्से तक के अधिकतम एक सौ बीस दिनों के विशेषाधिकार अवकाश के बराबर राशि का भुगतान किया जा सकता है।"

14. उक्त विनियम के विनियमन 41 में,-

(i) उप विनियमन (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(1) 01 नवंबर 2012 को और उस तिथि से, जहां कहीं भी किसी अधिकारी को झूठी पर यात्रा करने की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे : -

(ए) कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड का एक अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने का पात्र है:

यह भी कि वह हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यापार की अत्यावश्यकताओं या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी गई हो:

(बी) मध्य प्रबंधन ग्रेड का एक अधिकारी ट्रेन से प्रथम श्रेणी या एसी 2-टियर स्लीपर से यात्रा करने का पात्र है:

यह भी कि वह हवाई (इकोनॉमी क्लास) से यात्रा कर सकता है यदि यात्रा की जाने वाली दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है:

यह भी कि वह कम दूरी की हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) भी कर सकता है, यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं या सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा करने की अनुमति दी जाती है;

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक ग्रेड का एक अधिकारी ट्रेन की एसी प्रथम श्रेणी में या हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास) करने का पात्र है;

(डी) वरिष्ठ प्रबंधन या शीर्ष कार्यपालक ग्रेड का एक अधिकारी हवाई या रेल से न जुड़े हुए स्थानों के बीच कार से यात्रा कर सकता है बशर्ते यह दूरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो:

यह भी कि जब दो स्थानों के बीच की दूरी का एक बड़ा हिस्सा हवाई या रेल द्वारा कवर किया जा सकता है, तो बाकी की दूरी सामान्य रूप से कार द्वारा तय की जानी चाहिए;

(ई) किसी अन्य अधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यवसाय की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने वाहन या टैक्सी या बैंक के वाहन से यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;

(एफ़) किसी भी ग्रेड या स्केल का अधिकारी सड़क या हवाई या रेल से न जुड़े हुए स्थानों के बीच डीलक्स केबिन श्रेणी में जल परिवहन द्वारा यात्रा करने के लिए पात्र होगा।”;

(ii) उप विनियम (4) में, खंड (ए) के लिए, निम्न खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“(ए) 01 जून, 2015 को और उस तिथि से हाल्टिंग भत्ता, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में निर्धारित ग्रेड या स्केल के अधिकारी, कॉलम (2) में निर्धारित दरों पर 'प्रतिदिन' निम्नलिखित भत्ते का पात्र होगा: -

तालिका

अधिकारियों का स्केल / ग्रेड	मेट्रो (रुपए)	'ए' श्रेणी के बड़े शहर (रुपए)	क्षेत्र - 1 (रुपए)	अन्य स्थान (रुपए)
स्केल VI व उससे ऊपर के अधिकारी	1800	1300	1 100	950
स्केल IV व V या उससे ऊपर के अधिकारी	1500	1300	1 100	950
स्केल I/II/III के अधिकारी	1300	1100	950	800

यह भी कि यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम लेकिन चार घंटे से अधिक हो, तो उक्त दरों का आधी दर से हाल्टिंग भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण – हाल्टिंग भत्ते की गणना के लिए "प्रतिदिन" का मतलब चौबीस घंटे या उसके बाद के किसी भी भाग की प्रत्येक अवधि होगी, हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, "प्रतिदिन" का तात्पर्य आठ घंटे से कम नहीं होगा।"

15. उक्त विनियमों के विनियम 42 में, उप विनियमन (3) के लिए निम्नलिखित उप विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"(3) जून 2015 के पहले दिन को और उस तिथि से, स्थानांतरण पर एक अधिकारी पैकिंग के साथ स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा, आदि खर्चों के लिए एकमुश्त राशि के भुगतान का पात्र होगा, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट किया गया है:-

तालिका

स्केल	एकमुश्त राशि
उच्च कार्यपालक तथा वरिष्ठ प्रबंधन (स्केल IV तथा उससे ऊपर के अधिकारी)	रु. 20,000
मध्य प्रबंधन तथा कनिष्ठ प्रबंधन (स्केल III तक के अधिकारी)	रु. 15,000."

16. उक्त विनियम के विनियम 44 में, उप विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(3) चार वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक के दौरान, एक अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक ब्लॉक में एक बार अपने स्थायी निवास स्थान की यात्रा के लिए अवकाश यात्रा रियायत का पात्र होगा:

यह भी कि वह दो वर्ष के एक ब्लॉक में अपने स्थायी निवास स्थान की और दो वर्ष के दूसरे ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान की यात्रा कम दूरी के रास्ते से कर सकता है;

यह भी कि 1 जून 2015 से, वैकल्पिक रूप से, एक अधिकारी, चार वर्ष के ब्लॉक या दो वर्ष के ब्लॉक के दौरान कभी भी एक विकल्प का उपयोग करके, जैसा कि मामला हो, अपने एलटीसी (स्थायी निवास स्थान की यात्रा के अलावा) को यात्रा न करके सरेंडर और एनकैश कर सकता है, जिसके लिए वह ट्रेन से यात्रा के वर्ग के लिए पात्र किराया के बराबर राशि प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसके लिए वह जेएमजी स्केल-I और एमएमजी स्केल-II एवं III के अधिकारी के लिए 4500 किमी. (एक तरफ) और एसएमजी स्केल-IV एवं उससे ऊपर के अधिकारी के लिए 5500 किमी (एक तरफ) की दूरी तक पात्र है:

यह भी कि 1 जून 2015 से, एक अधिकारी जो अपने एलटीसी को एनकैश करने का विकल्प चुनता है, वह केवल अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए उस ब्लॉक/ टर्म में केवल एक बार ही इस तरह के नकदीकरण का लाभ उठा सकता है। एलटीसी की नकदीकरण सुविधा प्राप्त करते समय अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाते हुए साधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

(3ए) अधिकारी द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का लाभ उठाने के संबंध में माध्यम और श्रेणी वही होगा जिसके लिए अधिकारी समान्यतः स्थानांतरण के समय पात्र होता है और अवकाश यात्रा रियायत का लाभ के अधीन अन्य नियम व शर्तें समय-समय पर बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयों के अनुसार होंगे:

यह भी कि 1 मई 2010 से, कनिष्ठ प्रबंधन ग्रेड स्केल-I का अधिकारी अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय न्यूनतम किराये वाली इकाई क्लास में हवाई यात्रा करने का पात्र होगा। ऐसे मामले में वास्तविक किराए या की गयी यात्रा की दूरी हेतु, एंसी-प्रथम श्रेणी के लिए लागू किराए, इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यही नियम 1000 किमी से कम दूरी के लिए अवकाश यात्रा रियायत का लाभ लेते समय मध्य प्रबंधन ग्रेड स्केल-II और III के अधिकारी पर भी लागू होंगे।

17. उपरोक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची होगी:-

अनुसूची

[विनियम 23(2) देखें]

1 नवंबर, 2012 से कोई भी अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक इस भत्ते को समाप्त नहीं किया जाता है या उसमें पूर्णतया या आंशिक रूप से संशोधन नहीं किया जाता है, जैसा कि नीचे दी गयी तालिका में निर्दिष्ट है:-

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000 से कम वेतन	रु. 24,000 से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिज़ोरम (ए) चिमतुईपुई जिला और ऐसे क्षेत्र जो लुंगलेई जिले के लुंगलेई टाउन से 25 किमी से अधिक दूरी पर हों	2000	2600
	(बी) लुंगलेई टाउन से 25 किमी से ज्यादा दूर स्थित क्षेत्रों को छोड़कर पूरा लुंगलेई जिला	1600	2100
	(सी) सम्पूर्ण आईजोल जिला	1200	1500
2.	नागालैण्ड	1600	2100
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप (ए) उत्तर अंडमान, मध्य अंडमान, लिट्टिल अंडमान, निकोबार और नारकोन्डम द्वीप	2000	2600
	(बी) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	1600	2100
4.	सिक्किम	2000	2600
5.	लक्षद्वीप द्वीप	2000	2600
6.	असम	320	400

7.	मेघालय	320	400
8.	त्रिपुरा (ए) त्रिपुरा के कठिन क्षेत्र	1600	2100
	(बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण त्रिपुरा में	1200	1500
9.	मणिपुर	1200	1500
10.	अरुणाचल प्रदेश (ए) अरुणाचल प्रदेश के कठिन क्षेत्र	2000	2600
	(बी) कठिन क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश में	1600	2100
11.	जम्मू और कश्मीर (1) कठुआ जिला : नियाबत बानी, लोही, मल्हार और माछोडी	2000	2600
	(2) उधमपुर जिला : (i) डूडू बसंतगढ़, लंदर भमग इलाका, भाग 2(बी) में शामिल क्षेत्र को छोड़कर	2000	2600
	(ii) मोहरे तहसील में कम्बन क्षेत्र से गोयल क्षेत्र तक और कैसी क्षेत्र से अरनास क्षेत्र तक	1600	2100
	डोडा जिला : किशतवार तहसील में पद्देर और निबत नौगम के इलाके	2000	2600

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000 से कम वेतन	रु. 24,000 से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	लेह जिला : जिले में सभी स्थान	2000	2600
	बारामुल्ला जिला: (i) सम्पूर्ण गुरेज – निराबत, तंगदार सब-डिवीजन और केरन इलाका	2000	2600
	(ii) मच्चिल	1600	2100
6	पुंज और राजौरी जिला : पूँछ और राजौरी जिले को छोड़कर पूँछ और राजौरी जिलों के क्षेत्र तथा सुंदरबनी और दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्र	1200	1500

7	उपरोक्त (1) से (6) में जो क्षेत्र शामिल नहीं हैं, लेकिन जो वास्तव में नियंत्रण रेखा से 8 किमी के अंतर्गत हैं अथवा ऐसे स्थल जो राज्य सरकार द्वारा अपने स्टाफ के लिए समय-समय पर बार्डर भत्ते के लिए पात्र क्षेत्र घोषित किए गए हों।	1200	1500
12.	हिमाचल प्रदेश (1) चम्बा जिला (ए) पांगी तहसील, भरमार तहसील, पंचायत : बडगांव, बजौल, देओल कुगती, नयागाम और तुंदाह ग्राम: जगत ग्राम पंचायत का घातु, चौहटा ग्राम पंचायत का कनारसी	2000	2600
	(बी) भरमार तहसील, उपरोक्त (ए) मद में दिये गये पंचायत और गांवों को छोड़कर।	1600	2100
	(सी) भटियात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बानीखेत प्रापर को सम्मिलित कर)	1200	1500
	(2) किन्नौर जिला (ए) आसरंग, चितकुल और हांगो कूनो/चारंग पंचायत, 15/20 क्षेत्र में छोटा खंबा, नाथपा और रूपी ग्राम पंचायत, पूह उप-खंड, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर	2000	2600
	(बी) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा पूरा जिला	1600	2100
	(3) कुल्लू जिला : (ए) निरमांड तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें खारगा, कुश्वर और सारगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं।	2000	2600
क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000 से कम वेतन	रु. 24,000 से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	(बी) आउटर-सराज (निरमांड तहसील में जकात-खाना और बुरो गाँव को छोड़कर) और सम्पूर्ण जिला, आउटर-सराज और पंद्रहवीस के परगना को छोड़कर, लेकिन तहसील निरमांड के बुरो और जगत-खाना गावों को सम्मिलितकर	1200	1500
	(4) लाहौल और स्पीति जिला : लाहौल और स्पीति का पूरा क्षेत्र	2000	2600

	(5) शिमला जिला :		
	(i) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लवाना सदाना, सरपारा और चडी - बरांडा पंचायत शामिल हैं।	2000	2600
	(ii) दोरा-कवर तहसील, रामपुर में डरकाली ग्राम पंचायत, कशपथ तहसील और मुनीश, परगाना सराहन की घोरी चैबिस।	1600	2100
	(iii) चोपाल तहसील और घोरिस, पंजगांव, पटसनौ, नौबिस और परगाना सराहन की तीन कोठी, तकलेश क्षेत्र की देओथी ग्राम पंचायत, परगाना बराबिस, रामपुर तहसील का रामपुर कस्बा और परगाना रामपुर का घोरी नोग, शिमला कस्बा और उसका नगर परिसर (धाली, जतोग, कसुम्पति, मशोब्रा, तारादेवी और टूट)	1200	1500
	(6) कांगडा जिला :		
	(ए) बडा भंगाल और छोटो भंगाल के क्षेत्र	1600	2100
	(बी) कांगडा जिले का धर्मशाला कस्बा और नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कस्बे लेकिन धर्मशाला कस्बे में शामिल - विमेन्स आईटीआई, दारी, मेकानिकल वर्कशॉप, रामनगर, शिशु कल्याण और शहर एवं देश आयोजना कार्यालय, सकोह, लोअर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगडा दूध आपूर्ति योजना, दूगैर, एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, आंचलिक (जोनल) मलेरिया कार्यालय, दारी वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्ट्री, दारी, आई.पी.एच. उप-खण्ड, दान, निपटान (सेटलमेंट) कार्यालय, शामनगर, हिनवा प्रोजेक्ट, शामनगर।	1200	1500
	पालमपुर के एचपीकेवीवी कैम्पस समेत कांगडा जिले का पालमपुर शहर और नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय लेकिन पालमपुर शहर में शामिल - एच.पी.कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, मवेशी विकास कार्यालय/जेर्सी फार्म, बनूरी रेशमीपालन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि वर्कशाप/एचपीपीडब्ल्यूडी प्रभाग, बुंदला, इलेक्ट्रिकल उप-खंड, लोहना, डी.पी.ओ. निगम, बुंदला, इलेक्ट्रिकल एचईएसईई प्रभाग, घुग्गर।	1200	1500

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु. 24,000 से कम वेतन	रु. 24,000 से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
	(7) मण्डी जिला :		
	जोगिन्दरनगर तहसील की छहार वैली, बग्रा, चत्री, छोटधार, गरागुशैन,	1200	1500

	गाटू, गरयास, जंगैहली, जरयार, जोहर, कल्हानी, कल्वां, खोलनल, लोथ, शिल्हीबाग, सोमाचन, धचधर, टाची, थाना वी धुनांग तहसील की पंचायतें, धर्मपुर की पंचायतें ब्लॉक – बिंगा, कमलाह, सकलाना, टनयार और ताराखोलाह की पंचायतें, करसोग तहसील – बालीधर, बग्रा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुडी, मांज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें – बोही, बटवारा, धान्यारा, पौराकोठी, सेरी और शौजा।		
	(8) सिरमौर जिला : बानी, बखाली (पछड़ तहसील), भारोग भेनेरी (पैनता तहसील), बिरला (नहान तहसील), दिब्बेर (पछड़ तहसील) और थाना कसौगा (नहान तहसील) और थानसगीरी भूभाग की पंचायतें	1200	1500
	(9) सोलन जिला : मंगल पंचायत	1200	1500
	(10) उपरोक्त (1) से (9) तक की मदों में शामिल नहीं किए गए हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र	320	400
13.	उत्तर प्रदेश: चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तर काशी जिलों के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र।	2000	2600
13.	उत्तराखण्ड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चम्पावत जिलों के अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र।	2000	2600

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इन विनियमों में दिये गए पूर्वव्यापी प्रभाव इंडियन बैंक के अधिकारियों को वेतन और अन्य भत्तों एवं लाभों से संबन्धित है और अनिवार्य रूप से लाभकारी विधान है। अतः इन विनियमों के उक्त प्रावधानों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से इसके क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति के हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री धनराज. टी. महाप्रबन्धक (सीडीओ)

[विज्ञापन. -III /4/ असा./687/2021-22]

नोट: विनियम में किए गए संशोधनों को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया और तदनुसार निम्नांकित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया :

क्र.सं.	सं. एस ओ	दिनांक	प्रकाशन की तिथि
1	SRC/17/97	12.05.1997	31.05.1997
2	SRC/223/38	07.03.2000	16.03.2000
3	SRC/223C	07.08.2001	25.08.2001
4	1	04.01.2003	04.01.2003
5	72	01.05.2006	15.04.2011
6	157	16.10.2006	26.10.2011
7	IRC/G-9/2017-18	13.11.2017	11.01.2018

**INDIAN BANK
NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd March, 2022

F.No. IB/G-9/2021-22 (E).—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Indian Bank after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Indian Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2022.
(2) Save as provided in these regulations, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of November, 2012.

2. In the Indian Bank (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3, for clause (f), the following clause shall be substituted, namely :-

‘(f) "family" means the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children), wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters, and parents wholly dependent on the officer and in the case of married female officer may include her natural parents or parents-in-law, but not both.

Explanation. – “wholly dependent” shall mean such member of the family having an income not exceeding Rs. 10,000 per month and where the wholly dependent family members are parents, the income of any parent or aggregate income of both the parents if exceeds Rs. 10,000 per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer;’.

3. In regulation 4 of the said regulations, for sub-regulation (6), the following sub-regulations shall be inserted, namely: –

“(6) With effect from the 1st November 2012, the scales of pay specified against each grade shall be as under:

- (a) Top Executive Grade

Scale VII = Rs. 76520 - 2120/4 - 85000

Scale VI = Rs. 68680 - 1960/4 – 76520

- (b) Senior Management Grade

Scale V = Rs. 59170 - 1650/2 - 62470 - 1800/2 - 66070

Scale IV = Rs. 50030 - 1460/4 - 55870- 1650/2 – 59170

- (c) Middle Management Grade

Scale III = Rs. 42020 - 1310/5 - 48570 - 1460/2 - 51490

Scale II = Rs. 31705 - 1145/1 - 32850 - 1310/10 – 45950

- (d) Junior Management Grade

Scale I = Rs. 23700 - 980/7- 30560- 1145/2- 32850- 1310/7- 42020

Explanation – Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October, 2012 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2012 on stage- to- stage basis, or corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual.

- (7) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5) and (6) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

- (8) With effect from 1st day of November, 2012, officers shall be paid Special Allowance as under;

Scale I-III = 7.75% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV-V = 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI-VII= 11% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

Provided that nothing in this sub-regulation shall be construed as requiring the Bank to have at all times officers serving in this grade.

Note: The Special Allowance referred to in sub-regulations (8) with applicable Dearness Allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, –

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulations (1) shall be substituted, namely:–

“(1) Subject to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 4, on and from the 1st day of November, 2012, the increments shall be granted subject to the following, namely: –

- (a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (6) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;
- (b) one year after reaching the maximum in their respective Scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increment in the next higher scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management Grade Scale I who have moved to Middle Management Grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher scale, shall be eligible for four stagnation increments for every three completed years of service of which the first two shall be Rs.1310 each and next two Rs.1460 each;
- (d) officers in Middle Management Grade Scale II who have moved to Middle Management Grade Scale III in terms of clause (b) after reaching maximum of higher scale shall be eligible for three stagnation increments of Rs.1460 each for every three completed years of service and a fourth stagnation increment of Rs.1460 two years after receipt of third stagnation increment:

Provided that officers who have completed two years or more after receipt of the third stagnation increment shall be granted the fourth stagnation increment with effect from 1st day of May, 2015;

- (e) officers in substantive Middle Management Grade Scale III (those recruited in or promoted to Middle Management Grade Scale III) shall be eligible for three stagnation increments of Rs. 1460 each for every three completed years of service and fourth stagnation increment of Rs. 1460 to officers who have completed two years or more after releasing third stagnation increment as on 1st May 2015 and a fifth stagnation increment of Rs. 1460 two years after receipt of fourth stagnation increment provided that the officers who have completed two years after receipt of the fourth stagnation increment shall be granted the fifth stagnation increment with effect from 1st May 2015;
- (f) officers in Senior Management Grade Scale-IV shall be eligible for one stagnation increment of Rs. 1650 three years after reaching the maximum of scale with effect from 1st May 2015;

Provided that such increment shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

“*Explanation* – Grant of such increments in the next higher scale under this sub- regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

(ii) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (f) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:-

"(g) On and from the 1st day of November, 2012, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below:

TABLE

(1)	(2)
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers - Part I	Rs.670 per month one year after reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i) Rs.670 per month after one year after reaching maximum of the scale. (ii) Rs. 1680 per month, two years after reaching maximum of the scale:

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay shall be granted from the date of acquiring such qualification, the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.”;

(iii) in sub-regulation (3), after the table under clause (e), the following shall be inserted, namely:-

“(f) On and from the 1st November, 2012, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:

TABLE

Increment Component (Rs.)	Dearness Allowance as on 01.11.2012 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)
1310	143	1453
1460	159	1619
1650	180	1830
1800	196	1996
1960	214	2174
2120	231	2351

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under Column (3) of the tables in clauses (b), (c), (d), (e) and (f) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the table under clause (f) and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2), (3), (4), (5) and (6) of Regulation 4 is earned.
- (iii) Only Officers who were in the service of the bank on or before 1st November 1993 shall be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale of the pay they are placed.
- (iv) On and from the 1st November, 1999 there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:
Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after 1st November, 1999, it shall be released to the officer on and from that date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.
- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) of this sub-regulation shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e) or (f) above, one year after reaching the maximum of the scale.”.

5. In regulation 21 of the said regulations, after sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be inserted, namely:

“(6) On and from the 1st day of November, 2012, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.10% of Pay.

Explanation: – For the purposes of this sub-regulation,-

- (a) "pay" for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments plus Special Allowance;

(b) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in clauses (c), (d), (e), (f) and (g) to the explanation in sub-regulation (2) of regulation 5 shall rank for dearness allowance”.

6. In regulation 22 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November, 2012,—

- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.75 per cent of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following table, namely:—

TABLE

Where the place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)
(i) Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
(ii) Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
(iii) Other places	7.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.75 per cent of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above table.

NOTE: The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall also be restricted to 150 per cent of the House Rent Allowance as hitherto.”.

7. In regulation 23 of the said regulations,—

(A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5) , the following sub- regulations shall be substituted, namely:—

"(1) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable:—

TABLE

Places	Rate
(1)	(2)
(i) Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs. 870 per month
(ii) Places with population of five lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair.	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.600 per month.

(2) On and from the 1st day of November, 2012, the rates of Special Area Allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.

(3) On and from the 1st day of November, 2012, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.400 per month or Rs.350 per month according to the classification of area as Group A or Group B respectively.

(4) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs.1100 per month from the date he reports to the latter place up to the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of June, 2015, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent of pay subject to a maximum Rs.4000 per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.2000 per month:

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent of his pay subject to a maximum Rs.2000 per month.”;

- (B) for sub-regulation (8). the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(8) On and from the 1st day of November 2012, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.200 per month.”;

- (C) in sub-regulation (10),—

- (a) for the figures, letters and words “1st day of November 2007”, the figures, letters and words “1st day of November, 2012” shall be substituted;

- (b) for the table, the following table shall be substituted, namely:—

“TABLE

Place (1)	Rate (2)
(i) Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.750 per month
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs. 1000 per month
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.2000 per month”

8. In regulation 24 of the said regulations,—

- (i) for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st day of November 2012, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the table below, namely:—

TABLE

Grade (1)	Maximum limit of reimbursement (2)
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.8000 per annum or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.9050 per annum or the amount incurred whichever is less

Note: (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

- (ii) for the year 2012, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November 2012 and December, 2012.

(1A) An officer shall be eligible for Medical Insurance facility for self and his family, as per terms and conditions specified by the Board.”

9. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation(1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st day of November, 2012, a sum equal to

0.75 per cent, of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.15 per cent of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

10. In regulation 33 of the said regulations, for sub-regulation (4), the following sub- regulation shall be substituted, namely

"(4) On and from 1st June, 2015, Privilege Leave may be accumulated up to not more than two hundred and seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of two hundred and forty days:

Provided further that an officer desiring to avail privilege leave shall ordinarily give not less than fifteen days notice of his intention to avail of such leave.”.

11. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(4) On and from the 1st June 2015, Special Sick Leave up to thirty days may be granted to an officer once during his entire period of service for donation of kidney or organ.”.

12. In regulation 36 of the said regulations, for sub-regulations (2) and (3) , the following sub-regulations shall be substituted, namely:-

" (2) With effect from the 25th day of May 2015, leave may also be granted once during service to a childless female officer for legally adopting a child who is below one year of age for a maximum period of six months subject to the following terms and conditions: -

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
 - (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the officer shall produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
 - (iii) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy; and
 - (iv) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service.
- (3) With effect from the 25th day of May 2015, within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.”
- (4) Maternity leave, which shall be on substantive pay, shall be granted to a female officer for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that within the overall period of twelve months, leave may also be granted in case of miscarriage or abortion or Medical Termination of Pregnancy.

- (5) With effect from 1st day of June 2015, male officers having up to two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement which may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave shall be applied upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child.”

13. For regulation 38 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“38. Save as provided below, all leave to the credit of an officer shall lapse on resignation, retirement, death, discharge, dismissal or termination:

Provided that where an officer retires from the Bank's service, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he had accumulated:

Provided further that where an officer has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to emoluments of any period, not exceeding two hundred and forty days of privilege leave that he has accumulated:

Provided also that where an officer dies while in service, there shall be payable to his legal representatives, a sum equivalent to the emoluments for the period not exceeding two hundred and forty days of privilege leave to his credit as on the date of his death:

Provided also that where an officer resigns from service on or after 1st April, 2001 after giving due notice as in sub-regulation (2) of regulation 20, he may be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of one hundred and twenty days.”

14. In regulation 41 of the said regulations,—

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from 1st day of November 2012, wherever an officer is required to travel on duty, the following provisions shall apply, namely:—

- (a) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train:
Provided that he may, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;
- (b) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train:
Provided that he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kilometers:
Provided further that he may travel by air (economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest;
- (c) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class);
- (d) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 kilometers:
Provided that when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car;
- (e) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank’s vehicle;
- (f) an officer of any grade or scale shall be eligible to travel by water transport in deluxe cabin category between places not connected by road or air or rail.”;

(ii) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

“(a) On and from the 1st June, 2015, an officer in the Grades or Scales set out in column (1) of the table below shall be entitled to 'per diem' Halting Allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:—

TABLE

Grade / Scales of Officers	Metro (Rs.)	Major 'A' Class Cities (Rs.)	Area-I (Rs.)	Other Places (Rs.)
(1)	(2)			
Officers in Scale VI and above	1800	1300	1100	950
Officers in Scale IV and V above	1500	1300	1100	950
Officers in Scale I/II/III	1300	1100	950	800

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, the Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation – For the purposes of computing Halting allowance, "per diem" shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, "per diem" shall mean a period of not less than eight hours.”

15. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3). the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1st June 2015, an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grade/Scale	Amount
Top Executive and Senior Management Grade (Officers in Scale IV and above)	Rs.20,000
Middle Management and Junior Management Grade(Officers upto Scale III)	Rs. 15,000.”

16. In regulation 44 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his place of domicile once in each block of two years:

Provided that he may travel in one block of two years to his place of domicile and in another block of two years to any place in India by the shortest route;

Provided further that with effect from 1st June 2015, alternatively, an officer by exercising an option anytime during a four year block or two year block, as the case may be, surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to place of domicile) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled up to a distance of 4500 kilometers (one-way) for officers in JMG-Scale-I and MMG - Scale II and III and 5500 kilometers (one-way) for officers in SMG- Scale IV and above:

Provided also that with effect from 1st June 2015, an officer opting to encash his Leave Travel Concession, shall prefer the claim for himself and his family members only once during the block / term in which such encashment is availed of and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession is also available while encashing the facility of Leave Travel Concession.

(3A) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer, shall be as decided by the Board from time-to-time:

Provided that with effect from 1st May 2010 an officer in Junior Management Grade Scale I while availing Leave Travel Concession shall be entitled to travel by air in the lowest fare economy class in which case the reimbursement will be the actual fare or the fare applicable to AC 1st Class fare by train for the distance travelled whichever is less and the same rules shall apply when an officer in Middle Management Grade Scale II and Middle Management Grade Scale III while availing Leave Travel Concession where the distance is less than 1000 kilometers”

17. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

[See regulation 23(2)]

With effect from the 1st November, 2012, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the table below, namely:-

Special Area Allowance

Sr.No.	Area	Allowances (₹)	
		Pay below ₹24,000	Pay above ₹24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimpui District and areas beyond 25 kms. fromLunglei Town in Lunglei District.	2000	2600
	(b) Entire Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. fromLunglei	1600	2100

Sr.No.	Area	Allowances (₹)	
		Pay below ₹24,000	Pay above ₹24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
	town.		
	(c) Entire Aizawl District	1200	1500
2.	Nagaland	1600	2100
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	2000	2600
	(b) South Andaman (including Port Blair)	1600	2100
4.	Sikkim	2000	2600
5.	Lakshadweep Islands	2000	2600
6.	Assam	320	400
7.	Meghalaya	320	400
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	1600	2100
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	1200	1500
9.	Manipur	1200	1500
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	2000	2600
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	1600	2100
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District: NiabatBani, Lohi, Malhar and Machhodi	2000	2600
	(2) Udhampur District: a) DuduBasantgarh, Lander BhamagIllaqa, other than those included in Part 2(b).	2000	2600
	b) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	1600	2100
	(3) Doda District: Illaquas of Padder and NiabatNowgam in Kishtwar Tehsil	2000	2600
	(4) Leh District : All places in the District	2000	2600
	(5) Barmulla District (a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and KeranIllaqua	2000	2600
	(b) Matchill	1600	2100
	(6) Poonch and Rajouri District : Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts	1200	1500
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	1200	1500
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		

Sr.No.	Area	Allowances (₹)	
		Pay below ₹24,000	Pay above ₹24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
	(a) Pangi Tehsil, Bharmour Tehsil, Panchayats : Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram PanchayatJagat, Kanarsi of Gram PanchayatChauhata	2000	2600
	(b) Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in (a) above.	1600	2100
	(c) JhandruPanchayat in BhatiyatTehsil,Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	1200	1500
	(2) Kinnaur District:		
	(a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/ Charang Panchayats,15/ 20 Area comprising the Gram Panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rupi, PooH Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	2000	2600
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above.	1600	2100
	(3) Kullu District:		
	(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	2000	2600
	(b) Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabisbut including villages Jagat-Khana and Burrow of Tehsil Nirmand).	1200	1500
	(4) Lahaul and Spiti District : Entire area of Lahaul and Spiti	2000	2600
	(5) Shimla District :		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda.	2000	2600
	(b) Dora-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, GhoriChaibis of ParganaSarahan.	1600	2100
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of ParganaSarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, ParganaBarabis, Kasba Rampur and GhoriNog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Simla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	1200	1500
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bara Bhangal and ChhotaBhangal	1600	2100
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur Town of Kangra District including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. KrishiVishwavidhalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German	1200	1500

Sr.No.	Area	Allowances (₹)	
		Pay below ₹24,000	Pay above ₹24,000
(1)	(2)	(3)	(4)
	Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar		
	(7) Mandi District: Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	1200	1500
	(8) Sirmaur District: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), BharogBheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	1200	1500
	(9) Solan District : MangalPanchayat.	1200	1500
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	320	400
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts	2000	2600
14.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat Districts	2000	2600

EXPLANATORY MEMORANDUM

The retrospective effect given in these regulations relate to the pay and other allowances and benefits to the officers of the Indian Bank and are essentially beneficial legislation. Hence, giving retrospective effect to the said provisions of these regulations will not adversely affect the interest of any person as a result of such retrospective application.

SRI. DHANARAJ. T, General Manager (CDO)

[ADVT. III /4/Exty./687/2021-22]

Foot Note: The amendment regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 and were subsequently amended *vide* the following notifications, namely:-

S. No.	No. S.O.	Dated	Date of Publication
1	SRC/17/97	12-05-1997	31-05-1997
2	SRC/223/38	07-03-2000	16-03-2000
3	SRC/223C	07-08-2001	25-08-2001
4	1	04-01-2003	04-01-2003
5	72	01-05-2006	15-04-2011
6	157	16-10-2006	26-10-2011
7	IRC/G-9/2017-18	30.11.2017	11-01-2018